International Journal of Applied Research 2016; 2(12): 89-91

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(12): 89-91
www.allresearchjournal.com
Received: 16-10-2016
Accepted: 17-11-2016

Dr. Archana Agrawal
Asst. Professor, Dept. Of Management Studies Dr. C.V. Raman University Kargiroad, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh, India

Shilpi Kesharwani
M.Phil Scholar, Dr.C.V.Raman University Kargiroad, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh, India

Correspondence
Dr. Archana Agrawal
Asst. Professor, Dept. Of Management Studies Dr. C.V. Raman University Kargiroad, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh, India

छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास योजना का प्रभाव बलौदा बाजार भाटापरा जिला के संदर्भ में

Dr. Archana Agrawal and Shilpi Kesharwani

सारांश
राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रयासों के परिणामस्वरूप 16 अगस्त 2007 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को स्वीकृती प्रदान कर दी। इस योजना हेतु सरकार द्वारा पांच वर्ष के लिये 25000 करोड़ आवंटित किये गये हैं।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का सम्पुर्ण विकास सुनिश्चित करके ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि मे 4 प्रति. की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है। कृषि विकास योजना राज्य की आयोजना होगी। और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों पर उपगत आधारित ब्यय की प्रतिशतता के अतिरिक्त इस योजना के तहत सहायता के लिये पात्रता कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के लिये बजटों में रखी गयी राशि पर निर्भर होगी। कृषि विकास योजना के तहतुकेन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को 100 प्रति अनुदान के रूप में कोष प्रदान किया जाएगा।

मूल शब्दः कृषि विकास योजना, बजटों, सम्पुर्ण विकास

प्रस्तावना
बलौदाबाजारः भाटापारा जिला प्राकृतिक संसाधनों से समक्ष है यहां की उर्वरा भुमि विभिन्न फसलों के लिये उपयुक्त पायी गयी है। विभिन्न फसलों के लिए यहां का जलवायु एवं मेहनती किसान इस जिला की पूंजी है। नया जिला निर्माण के बाद कृषि विकास एवं कृषि विज्ञान केन्द्र भाटापारा के मार्गदर्शन में कृषकों द्वारा अपनायी जा रही कृषि विकास योजना से कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है। बलौदाबाजार भाटापारा जिला में छः विकास खण्ड शामिल किया गया है यहां की भौगोलिक स्थिति भिन्न होने के बाद भी यह जिला प्रत्येक वर्ष अपनी उत्तरोत्तर विकास की नयी उचाई कि ओर अग्रसर है कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर योजनाओं को गांव गली एवं खेत तक पहुंचाया जा रहा है।

कृषि विकास योजना का उद्देश्य
1. राज्यो को प्रोत्साहित करना ताकि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की जा सके।
2. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की योजनाओं के आयोजन और कार्यान्वयन की प्रक्रीया में राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना।
3. जलों और राज्यों के लिये कृषि योजनाओं की तैयारी की उपलब्धता पर सुनिश्चित करना।
4. यह सुनिश्चित करना की स्थानिय जरूरतों/फसलों/प्राथमिकताओं को राज्यों की कृषि योजनाओं में बेहतर ढंग से प्रतिबंधित किया जाए
5. मध्यस्थों को सकेन्द्रित करके महत्वपुर्ण फैसलों में पैदावार के अंतर को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करना
6. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम रिटर्न दिलाना।

भारतीय कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी
1. भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51 फीसदी भाग पर कृषि, 4 फीसदी पर पर चरागाह, लगभग 21 फीसदी पर वन और 24 फीसदी बंजर और बिना उपयोग की है.
2. देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52 फीसदी भाग कृषि और इससे सम्बंधित उद्योग और धंधों से अपनी आजीविका चलता है.

3. 2004–2005 में भारत के निर्यात में कृषि और सम्बंधित वस्तुओं कानुपात लगभग 40 फीसदी रहा।
4. विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है. भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के करीब 47 फीसदी भाग पर चावल की खेती की जाती है।
5. विश्व में गेहूँ उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है. देश की कुल कृषि योग्य जमीन के लगभग 15 फीसदी भाग पर गेहूँ की खेती की जाती है।
6. देश में गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है।
7. हरित क्रांति (Green Revolution) का सबसे अधिक प्रभाव गेहूँ और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना गेहूँ के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई।
8. भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967–1968 में हुई।
9. प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983–1984 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ।
10. तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई।
11. भारत विश्व में उर्वरक (फर्टिलाइजर) का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है।
12. पोटाशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है।
13. आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है।
14. फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है।

शोध अध्ययन का महत्व

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी कृषि विकास की योजनाओं को खेतों तक पहुंचाया एवं समग्र विकास की उंची सोपान तक जिला को अग्रसर बढ़ाना है। उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि हेतु योजना कि सफलता का मुल्यांकन करना कृषकों की जरूरतों को पूरा करना बाजार व्यवस्था सुनिश्चित करने में कृषकों द्वारा सुझायी गयी समस्या का निदान हेतु प्रयास करना कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देना सस्ती सुदंर व टिकाउ खेती की ओर कृषकों को बयान आकृष्ट कराना जिसमें आर्थिक स्थिति में सुधार एवं जिला तथा राज्य का कल्याण होता है। सुनिश्चित करने हेतु इसे शोध का विषय बनाया गया है।

साहित्य की समीक्षा

साहित्य की समीक्षा के अध्ययन में विद्वानों का अनुभव सीमित है। अनुसंधान के चयनित क्षेत्र में साहित्य का एक संग्रह शामिल है। अतीत में कृषि क्षेत्र में प्रदर्शन से संबधित विभिन्न अध्ययन शोधकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया है।

- जाखरे एवं मजूमदार (1964) ने अपनी पुस्तक "Response of agriculture producers to prices" ने कहा– समानुपात में फेरबदल के द्वारा क्षेत्रफल को बदला जा सकता है। इस प्रकार फसल के उत्पादन वृद्धि में क्षेत्रफल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
- चौरसिया एवं सिंह (1972) ने अपनी पुस्तक "Indian journal of agriculture economics'' में कहा कि– सामान्य फसलों की तुलना में उच्च उत्पादक फसलों में अधिक खाद एवं मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। जिसके फलस्वरूप उपज की मात्रा में वृद्धि होगी। परिणामतः उत्पादक को लाभ होगा।
- मिश्रा सी.एस. (1978) द्वारा अपनी पुस्तक ''problem of Agriculture Development in chhattisgarh Region of madhyapradesh'' में बताया गया है कि– लेखक ने वर्ष 1950–51 से 1974–75 के लिए मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कृषि विकास का अध्ययन किया है। अपने अध्ययन के विश्लेषण से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि संपूर्ण मध्यप्रदेश एवं विशेष रूप से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कृषि विकास एवं उत्पादकता की दर को बढ़ाने का प्रयास किया है।
- सिंह एवं पांडे (1981) ने अपनी पुस्तक ''agriculture situation in india'' में कहा कि–

1. अनाजों की उत्पादकता बहुत अधिक मात्रा में खदों के उपयोग तथा सिंचाई सुविधाओं पर निर्भर है।
2. राज्य में पिछले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादन में वृद्धि मुख्य रूप खादों के उपयोग में वृद्धि का परिणाम है।
3. फसलों के उत्पादकता की अस्थिरता में वृद्धि खादों के उपयोग की गिरती प्रवृत्ति को दिखाता है।

- कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय 2014 द्वारा दी गई रिपार्ट "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" में बताया गया है कि उपर्युक्त प्रेक्षण के अनुसरण में और योजना आयोग के साथ परामर्श से कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2007–2008 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरूआत की थी। जो तब से प्रचलन में है।

तालिका 1: किसानों के द्वारा अपनाई गई कृषि योजना

क्रमांक	योजना का नाम	संख्या	प्रतिशत
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	34	34
2.	सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना	15	15
3.	कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना	18	18
4.	फसल प्रदर्शन योजना	19	19
5.	कृषक समग्र विकास योजना	7	7
6.	योजना न अपनाने वाले किसान	7	7
7.	कुल योग	100	100

शोध क्रियाविधि

स्रोत : प्रश्नावली के माध्यम से संग्रहित समंक।

उपरोक्त सारणी एवं चित्र के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 100 किसानों में से सर्वाधिक संख्या (34) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को अपनाने वाले किसानों की है। वहीं सबसे कम संख्या (7) कृषक समग्र विकास योजना को अपनाने वाले किसानों की है। दूसरे क्रम पर फसल प्रदर्शन योजना, को अपनाने वाले किसानों की संख्या है तो तीसरे क्रम पर कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना अपनाने वाले किसान है तथा सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना को अपनाने वाले किसानों का क्रम चौथा है। वहीं 7 किसानों ने किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया है।

सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि उक्त योजनाओं को लगभग सभी किसानों ने एक – एक योजना को अपनाया है।

शोध विषय की परिकल्पना

शून्य–परिकल्पना की जाँच

1. कृषक बलौदाबाजार भाटापारा कृषि कार्यालय द्वारा प्रदत्त योजनाओं से संतुष्ट है।

सारणी क्रमांक 4 के विष्लेषण से स्पष्ट है कि राज्य सरकार के द्वारा बलौदा बाजार, भाटापारा क्षेत्र में संचालित योजनाओं से 58 प्रतिशत किसान पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। वहीं 27 प्रतिशत किसान आंशिक रूप से संतुष्ट थे। तो 15 प्रतिशत किसानों को योजना अपनाने में कठिनाई गई। जिसके पीछे योजना की पूर्ण जानकारी

न होना है। इनमें संतुष्टि का जो परिणाम आना चाहिए था वह नहीं पाया गया। अतः हमारी प्रथम शून्य–परिकल्पना कि कृषक बलौदाबाजार, भाटापारा कृषि कार्यालय द्वारा प्रदत्त योजनाओं से संतुष्ट है आंशिक सत्य साबित होती है।

2. बलौदाबाजार–भाटापारा जिले में विभिन्न सुविधाएं कृषकों के हित हेतु प्रदान की गयी है।

शोध अध्ययन से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बलौदाबाजार–भाटापारा जिले में कृषकों के विकास के लिए, कृषि के विकास एवं इनके हितों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। जिनका लाभ कृषकों प्राप्त हो रहा है। साथ ही राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी संचालित है जो सूखा, अतिवृष्टि बाढ़ आदि में कृषकों के आर्थिक हितों को सुरक्षा प्रदान करती है। अतः अध्ययन से यह साबित होता है कि हमारी दूसरी शून्य–परिकल्पना – बलौदाबाजार–भाटापारा जिले में विभिन्न सुविधा, कृषकों के हित हेतु प्रदान की गयी है सत्य साबित होती है।

3. कृषकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं से कृषक लाभन्वित होता है।

सारणी क्रमांक 2 के आधार पर हमारी तीसरी शून्य–परिकल्पना कृषकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं से कृषक लाभान्वित होता है भी सत्य साबित हुई है। बलौदा बाजार, भाटापारा क्षेत्र में सर्वेक्षित किसानों में इनके कल्याण एवं विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में औसत से अधिक किसान इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं।

4. कृषि संबंधित योजनाओं की कृषकों को पुरी जानकारी है।

शोध अध्ययन की अंतिम और चौथी शून्य–परिकल्पना– कृषि संबंधित योजनाओं की कृषकों को पुरी जानकारी है भी सत्य साबित होती है जिसका आधार सारणी क्रमांक 3 है। जिससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार एवं स्थानीय सत्ता के द्वारा किसानों के कल्याणार्थ संचालित इन योजनाओं का प्रचार–प्रसार ठीक तरह से किया गया है। जिस कारण से संबंधित व्यक्ति/किसान तक यह जानकारी पहुंच पाई है व जिससे वे लाभान्वित हुए हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक कृषक जो कि राज्य एवं जिले के विकास का केन्द्र है उसके विकास एवं कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की गई हैं। जिनकी जानकारी संबंधित किसानों को भी है। परन्तु इस का लाभ कैसे लिया जाए इस बात की कमी अध्ययन के दौरान सामने आयी है जिस कारण इनमें लाभ का स्तर अपेक्षा से कम पाया गया है।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ राज्य के साथ–साथ बलौदाबाजार, भाटापार जिले की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, यह ग्रामीण आजीविका की रीढ़ का काम करती है। कृषि विकास का अन्य क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जिससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था और आबादी का एक बहुत बड़ा भाग लाभ प्राप्त करता है, परन्तु इन सबके पीछे जिसकी मुख्य भूमिका होती है वह कृषक है। जो भूखे पेट कार्य करता है और उसे आंधी व धूप में आराम का ज्ञान नहीं है, वह हमारे लिए अन्न का उत्पादन करता है परन्तु स्वयं भूखा रहता है। वह हमारी दुधारू गायों को खिलाता है परन्तु उसे कांजी व पानी के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं मिलता। वह हमारे गोदामों को आनाजों से भरता है, परन्तु वर्ष भर प्रतिदिन का राशन मांगता है।

आजादी के बाद से आज तक किसानो एवं कृषि के विकास के लिए केन्द एवं राज्य सरकारों के द्वारा अनेकों योजनाओं का निर्माण एवं संचालन किया गया है। परन्तु हमारा किसान आज भी इन योजनाओं के वास्तविक लाभ से वंचित है। आज भी अधिकांश गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा है जो आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। ऐसे में जरूरत है योजनाओं के सही ढंग से क्रियान्वयन की। हमारी विडंबना है कि यहां सरकार की ओर से योजनाएं तो काफी बनती है लेकिन उनमें से ज्यादातर सफल नहीं हो पाती है। इनकी असफलता के पीछे की मुख्य वजह रणनीति और इच्छाशक्ति का आभाव होना है। किसानों की समस्याएं साल–दर–साल बढ़ती ही जा रही है। अतः जरूरत इस बात की है कि जिले में किसानों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिसमें उन्हें लगे कि सरकार या राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही संस्थाएं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत है।

सुझाव

- **योजनाओं के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकताः** जिले में किसानों के कल्याण एवं खेती के विकास हेतु संचालित योजनाएं संबंधित विभागों की लालफीताशाही के चलते वास्तविक लोगों की पहुँच से दूर है। अत : इनका व्यापक स्तर पर, स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जाए जिससे प्रत्येक किसान तक उसकी जानकारी पहुँचे और वे इन योजनाओं का लाभ ले सकें।
- **लैब टू लैण्डः** किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, खेती उन्नति का आधार बने इसके लिए कृषि अनुसंधान केन्द्रों में होने वाले अनुसंधानों को किसानों के समक्ष उनकी भूमि में ही किया जाए जिससे ये प्रशिक्षित भी होंगे व उसे अपना भी सकेंगे।
- ईमानदारी के साथ योजनाओं को संचालित करें।

संदर्भ ग्रंथ सुची

1. कृषि दिग्दर्शिका संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ (लेखक प्रताप कृदत्त)
2. योजना दर्शिका 2016 (लेखक एस.आर. केरकेट्टा)
3. कृषि यंत्र परिचय एवं उपलब्ध सुविधा (डॉ. अजय वर्मा)
4. छत्तीसगढ़ खेती (डॉ. जे.एस. उरकुरकर)
5. kisanhelp-in